

बिहार में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 30 मार्च 2025 को [अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस](#) के अवसर पर बिहार के पटना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्य बंदी

■ योजनाओं के बारे में:

- **अन्न भंडारण योजना:**
 - विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत पच्चीस [PACS \(प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ\)](#) में 62,500 मीटरकि टन की भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजना का शिलान्यास किया गया। जिस पर 83.16 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- **पुलिस भवन निर्माण:**
 - गृह विभाग के तहत कुल 133 पुलिस भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया। जिस पर 181.14 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है।
- **सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाएँ:**
 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 109.16 करोड़ रुपए है।
- **दीप नारायण सहि सहकारी संस्थान में छात्रावास:**
 - पटना में निर्मित एक छात्रावास का उद्घाटन किया गया, जिस पर 27.29 करोड़ रुपए की लागत आई है
 - **मखाना प्रोसेसिंग और विपिनन केंद्र**
 - समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत 46 लाख रुपए की लागत से **दरभंगा जिले मखाना प्रोसेसिंग और विपिनन केंद्र** का उद्घाटन किया गया।
- **पेयजल आपूर्ति योजनाएँ:**
 - नगर आवास और विकास विभाग की [अमृत-1 परियोजना](#) के अंतर्गत कुल 421.41 करोड़ रुपए की लागत से पाँच पेयजल आपूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया गया।

अमृत योजना क्या है?

■ परिचय:

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये **अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT)** 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी को कवर किया गया।
- मिशन का लक्ष्य **बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना** और चयनित शहरों क्षेत्र में सुधारों को लागू करना है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं।

■ अमृत 2.0 योजना:

- यह योजना 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई थी, जिसमें 5 वर्ष की अवधिानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये **अमृत 1.0** को शामिल किया गया है।
- इसमें देश के 500 शहरों से लगभग 4,900 वैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज शामिल है।
- अमृत 2.0 का उद्देश्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण द्वारा **शहर जल संतुलन योजना (City Water Balance Plan- CWBP)** के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- मिशन में शहरी नियोजन, शहरी वित्त को मजबूत करने आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिये सुधार एजेंडा भी शामिल है।

